औद्योगिक विकास को मिली गति तो सुधरने लगी अर्थव्यवस्था

खजाने की कीमत पर...

आनंद मिश्र ● जागरण

लखनऊ : भारत को पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन में स्वतः साझीदार बनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने की मुहिम छेड़ी है। प्रदेश के मौजूदा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को देखते हुए यह लक्ष्य बेहद मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए योगी सरकार की प्रतिबद्धता उम्मीद जगाने वाली है। बेहतर कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की मजबूत होती नींव पर औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलने से राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। बेहतर प्रोत्साहन नीतियों की बदौलत उत्तर प्रदेश ही उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां देश-विदेश के निवेशक ज्यादा से ज्यादा निवेश करने को आगे आ रहे हैं।

वर्ष 2017 में योगी के सत्ता संभालने के बाद वर्ष 2018 में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट में राज्य को 4.28 लाख करोड़ रुपये के एक हजार से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सरकार ने देश-दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जहां बुनियादी विकास पर भारी-भरकम राशि खर्च की वहीं औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति समेत करीब दो दर्जन सेक्टोरल पालिसी में बदलाव कर तमाम रियायतों का पिटारा खोला तो निवेशक भी पीछे नहीं रहे।

वर्ष 2022 में सत्ता में वापसी करने के बाद योगी ने फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआइएस) आयोजित करने का निर्णय किया। समिट में रिकार्ड 33.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए जो बढ़कर 40 लाख करोड़ रुपये पहुंच चुके हैं।

समिट में आए प्रस्तावों में से 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव धरातल पर भी उतर चुके हैं। निवेश सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित न रहे, इसके लिए योगी सरकार ने पूर्वांचल व बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए खास प्रोत्साहन देने की घोषणा करने के साथ ही बुंदेलखंड में नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया और पूर्वांचल व बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनवाए।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर एपी तिवारी बताते हैं कि पूरी दुनिया का अनुभव यह कहता है कि जैसे-जैसे विकास की गति बढ़ती है, वैसे-वैसे औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ती है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजनों से बड़ा बदलाव आया है। प्रो. तिवारी कहते हैं कि किसी भी प्रदेश के विकास में सरकार के बजट से कहीं अधिक निजी निवेश की भूमिका होती है। सरकार सिर्फ दिशा देने का काम करती है। वह कहते हैं कि यूपी में बढ़े निवेश को बैंकों के ऋण-जमा अनुपात से भी जाना-समझा जा सकता है। प्रदेश का ऋण-जमा अनुपात जून 2024 तक 60 प्रतिशत पहुंच गया है। यह औद्योगिक विकास का सबसे बड़ा सबूत है। निवेश बढ़ने से बेरोजगारी दर घटी है। वह यह भी कहते हैं कि खेती को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश के विकास की गति और तेज होगी। अखिलेश सरकार ने भी मुंबई में इन्वेस्टर्स कान्क्लेव किया था जिसमें करीब 33 हजार करोड़ के निवेश समझौते हुए थे। हालांकि, उनमें से ज्यादातर धरातल पर नहीं उतरे। उससे पहले बसपा सरकार में औद्योगिक निवेश बढ़ाने को लेकर कुछ खास पहल नहीं की गई।

4.28 लाख करोड़ के एक हजार से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे 2018 में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट में

33.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में

- निवेशकों को रास आ रहा उत्तर प्रदेश का बुनियादी विकास और प्रोत्साहन नीतियां
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से देश-दुनिया के निवेशकों का यूपी के प्रति बदला नजरिया
- अब देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी मजबूत उपस्थित दर्ज करा रहा उत्तर प्रदेश

निवेश का बड़ा हिस्सा कहां

क्षेत्र	प्रतिशत
पश्चिमांचल	52
पूर्वांचल	29
मध्यांचल	14
बुंदेलखंड	05

शीर्ष पांच जिलों का योगदान

जिला	प्रतिशत
गौतमबुद्धनगर	10
लखनऊ	04
आगरा	3.5
प्रयागराज	3.3
मेरठ	3.0

ऋण-जमा अनुपात में आया सुधार

वर्ष	अनुपात
मार्च 2018	53.23 प्रतिशत
मार्च 2019	52.18 प्रतिशत
मार्च 2020	51.60 प्रतिशत
मार्च 2021	51.71 प्रतिशत
मार्च 2022	52.38 प्रतिशत
मार्च 2023	54.54 प्रतिशत
मार्च 2024	58.72 प्रतिशत
जून 2024	60.03 प्रतिशत

ईज आफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग पर भी देना होगा ध्यान : नीरज सिंघल

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज सिंघल प्रदेश के औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए ईज आफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ ईज आफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग की बात भी करते हैं। कहा, जब तक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हालात सुगम नहीं होंगे और उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक औद्योगिक विकास सीमित दायरे में ही रहेगा। चीन जैसे देश सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से ही तेज विकास कर रहे हैं। प्रदेश में करीब 96 लाख एमएमएसई इकाइयां हैं, इनमें करीब 26 लाख प्रदेश सरकार के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत है, लेकिन फैक्ट्री एक्ट के तहत महज 14 हजार इकाइयां ही पंजीकृत हैं। यह आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं।